Volume-1, Issue-2, June 2025

ISSN: 3107-4243 (Online)
ISSN: (Print)
World View Research Bulletin
An International Multidisciplinary Research Journal

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की दिशा में बैंकिंग संस्थाओं का योगदान: एक संदर्भात्मक परीक्षण

स्वाति रावत, शोधार्थी [1] डॉ. ओ.पी. अरजरिया प्राध्यापक [2] (वाणिज्य)
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर(म.प्र.)

प्रस्तावना:

वर्तमान वैश्विक संदर्भ में जहाँ आर्थिक उन्नति की धारा निरंतर तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही है, वहाँ यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषतः ग्रामीण समुदाय—को उस प्रवाह की मुख्यधारा से सशक्त रूप से जोड़ा जाए। आर्थिक समावेशन अथवा वित्तीय समावेशन केवल एक आर्थिक नीति नहीं अपितु सामाजिक समानता की वह संरचना है जो वंचितों, पिछड़ों एवं सुदूरवर्ती जनों को आर्थिक अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनती है। यह प्रक्रिया मात्र बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है बल्कि यह आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक जीवन और सशक्त नागरिक भागीदारी की ओर अग्रसर एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक पहल है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और बहुलतावादी देश में जहाँ ग्राम्य जीवन ही सांस्कृतिक चेतना का मूलाधार है, वहाँ ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली का दृढ़ीकरण राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन की आधारशिला बन जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks) एक मध्यस्थ की भाँति कार्य करते हैं जो उन सामाजिक वर्गों तक पहुँच बनाते हैं जो अब तक परंपरागत बैंकिंग प्रणाली के परिधि से बाहर रहे हैं। ये बैंक न केवल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाते हैं, अपितु ऋण सुविधा, बीमा, पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे उपकरणों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस भूमिका निभाते हैं।

मध्यप्रदेश जो कि अपनी भौगोलिक विस्तार, प्राकृतिक विविधता तथा बहुस्तरीय सामाजिक संरचना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय प्रयास करता रहा है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक जैसे संस्थान, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न केवल आर्थिक सेवाओं को ग्राम्य जीवन से जोड़ने में अग्रणी रहे हैं अपितु उन्होंने जनमानस में वित्तीय जागरूकता, साक्षरता और स्वावलंबन की भावना को भी जागृत किया है।

यह शोध-पत्र इसी क्रम में मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सक्रिय बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका, उनके प्रभावक्षेत्र, अंतर्विरोधों एवं संभावनाओं का एक वैज्ञानिक, तात्त्विक और मानवीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन न केवल आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है वरन् भविष्य की संभावनाओं के लिए ठोस एवं व्यावहारिक सुझाव भी प्रदान करता है, ताकि वित्तीय समावेशन को केवल नीतिगत शब्दावली न रहकर, जीवन के यथार्थ से जुड़ा सामाजिक संकल्प बनाया जा सके।

यह प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि प्रस्तुत शोध-पत्र केवल शैक्षणिक औपचारिकता की पूर्ति न होकर, एक गहन सामाजिक प्रतिबद्धता का अभिव्यक्त रूप है एक ऐसी अंतःप्रेरणा जो हर ग्रामीण नागरिक को सम्मान, अवसर और आत्मगौरव के साथ राष्ट्र की प्रगति में सहभागी बनाने की भावना से प्रेरित है। यह शोध जनभागीदारी और न्यायपूर्ण आर्थिक विकास की इसी चेतना को समर्पित है।

शोध की पृष्ठभूमि:

विकासशील भारत की आर्थिक संरचना में आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) केवल एक नीति या सरकारी पहल न होकर, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य कदम है। यह विचार केवल आर्थिक व्यवस्था को सुधारने तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसे समतामूलक समाज के निर्माण का स्वप्न है जहाँ प्रत्येक नागरिक को आर्थिक संसाधनों तक समान पहुँच प्राप्त हो। भारत की विशाल जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी ग्रामीण अंचलों में निवास करता है, जहाँ लाखों लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। इस वंचना का कारण केवल भौगोलिक दूरी, सूचना का अभाव या संसाधनों की कमी नहीं है, अपितु

यह भी है कि परंपरागत बैंकिंग प्रणाली ने अपनी सेवाओं का विस्तार शहरी, संपन्न तथा सुविधा-संपन्न वर्गों के इर्द-गिर्द ही सीमित रखा।

भारत सरकार ने इस असंतुलन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि जैसी दूरगामी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिस मजबूत संरचना की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति ग्रामीण बैंकिंग संस्थाओं ने की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks - RRBs) इस दृष्टि से उस सामाजिक-आर्थिक सेतु की भाँति उभरे जिन्होंने न केवल बैंकिंग सेवाओं को गाँवों की चौपाल तक पहुँचाया, बल्कि आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण भी निर्मित किया। इन बैंकों की स्थापना ही इस ध्येय से हुई थी कि वे ग्रामीण जनों को कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, पशुपालन, स्व-रोज़गार तथा अन्य आजीविका के स्रोतों हेतु वित्तीय सहारा प्रदान करें। मध्यप्रदेश जैसे राज्य, जिसकी जनसंख्या का लगभग 70% भाग ग्रामों में निवास करता है और जहाँ आजीविका के प्रमुख आधार कृषि, श्रम, वन उपज एवं लघु व्यवसाय हैं वहाँ ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक जैसे संस्थान वित्तीय समावेशन को न केवल व्यवहार में उतार रहे हैं बल्कि वे एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान कर रहे हैं।

इस शोध का आधार भी इसी यथार्थ पर स्थित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन एक आर्थिक व्यवहार मात्र नहीं, बल्कि वह सामाजिक नवचेतना है जो निर्धनतम व्यक्ति को भी स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ती है। जब कोई ग्रामीण, जो पहले बैंक के द्वार से भी अपरिचित था, अब खाता खोलता है, ऋण लेता है, बीमा कराता है या पेंशन प्राप्त करता है तो यह प्रक्रिया उसे आर्थिक प्रवाह की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ-साथ उसकी सामाजिक स्थिति में भी उल्लेखनीय परिवर्तन लाती है। वह केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि मनवौज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर भी सशक्त होता है। यह शोध-पत्र इसी संदर्भ में यह विश्लेषण करता है कि किस प्रकार मध्यप्रदेश में सक्रिय ग्रामीण बैंकिंग संस्थाएँ वित्तीय समावेशन को यथार्थ और व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर रही हैं। यह अध्ययन उस सेतु संरचना की पड़ताल करता है जो ग्रामीण जनता और बैंकिंग सेवाओं के मध्य स्थापित है यह जानने का प्रयास करता है कि यह सेतु कहाँ सुदृढ़ है, कहाँ दुर्बल और इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु क्या ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। यह शोध केवल आँकड़ों का प्रस्तुतिकरण नहीं अपितु एक आश्वस्त भविष्य की दिशा में उठाया गया एक विवेकपूर्ण कदम है।

शोध की आवश्यकता एवं उद्देश्य:

वर्तमान समय में जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है तब डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल उपयोगिता, तकनीकी साक्षरता तथा डिजिटल विश्वास की आवश्यकता है। इसके अभाव में डिजिटल समावेशन एक चुनौती बन जाता है। इसी प्रकार किसानों, कारीगरों, लघु उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता या वे उच्च ब्याज दरों की वजह से बैंकों से दूर रहते हैं। यदि वे ऋण प्राप्त भी कर लें, तो उसकी समय पर वसूली भी एक जटिल समस्या बन जाती है। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण बैंकों की भूमिका, कार्यप्रणाली, उनकी योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन तथा सेवा गुणवत्ता का समग्र मूल्यांकन किया जाए।

यह शोध मध्यप्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में किया गया है जिससे यह समझा जा सके कि वे ग्रामीण समाज के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं उनका प्रभाव क्या है और उनके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं। यह अध्ययन नीतिनिर्माताओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है, जिससे ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को और अधिक सक्षम, सुलभ और उपयोगी बनाया जा सके।

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. मध्यप्रदेश में ग्रामीण बैंकों की भूमिका का समग्र मूल्यांकन करना।
2. ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता एवं उपयोगिता का अध्ययन करना।

3. **बैंकिंग सुविधाओं के प्रभाव से ग्रामीण जनजीवन में हुए सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों को पहचानना।**
4. **ग्रामीण बैंकों की वित्तीय कार्यप्रणाली जैसे ऋण नीति,** एनपीए प्रबंधन, डिजिटल सेवाओं **आदि का विश्लेषण करना।**
5. बैंक अधिकारियों, **कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं की राय एवं अनुभवों के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था की स्थिति** समझना।
6. **वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।**
7. वर्ष 2021 से 2025 **तक के आँकड़ों के आधार पर वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से ग्रामीण बैंकों की तुलना करना।**
8. **शासन व प्रशासन के लिए नीति निर्माण में सहयोग हेतु शोध आधारित निष्कर्ष एवं मार्गदर्शन प्रस्तुत करना।**

शोध पद्धति:

इस शोध कार्य की आधारशिला पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर अवलंबित है **जिसके अंतर्गत समस्त जानकारियाँ मध्यांचल ग्रामीण बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन-पुस्तिकाओं, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा प्रकाशित** प्राधिकारिक प्रतिवेदनों, **भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट,** विविध शोध-**पत्रिकाओं,** प्रासंगिक पुस्तकों **तथा अन्य प्रामाणिक ऑनलाइन संसाधनों से संगृहीत की गई हैं। इस अध्ययन में प्राथमिक डेटा जैसे** सर्वेक्षण, **साक्षात्कार अथवा अवलोकन का समावेश नहीं किया गया है। सम्पूर्ण शोधकार्य उन सूचनाओं के** विश्लेषणात्मक अध्ययन पर केंद्रित है **जो पूर्व में विश्वसनीय स्रोतों द्वारा प्रकाशित एवं संकलित की जा चुकी हैं।** यह कार्य साहित्यिक विवेचना, **सांख्यिकीय समीक्षा और नीतिगत बिंदुओं के विवेचनात्मक परीक्षण** के माध्यम से **निष्पक्ष और तथ्यात्मक निष्कर्षों तक** पहुँचने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष:

मध्यांचल ग्रामीण बैंक के विगत पाँच वर्षों (2020–21 से 2024–25) के द्वितीयक आँकड़ों का गहन विश्लेषण यह उद्घाटित करता है कि बैंक ने अपने वित्तीय प्रबंधन, **नीतिगत दिशा और कार्यदक्षता के विविध आयामों में प्रशंसनीय प्रगति अर्जित की है। शुद्ध लाभ में हुई सतत वृद्धि जो ₹102 करोड़ से बढ़कर ₹132 करोड़ तक पहुँची यह संकेत करती है कि बैंक ने न केवल आय-सृजन में प्रभावशीलता प्रदर्शित की है, बल्कि व्यय-नियंत्रण की दिशा में भी अनुशासित नीति अपनाई है। ऋण-जमा अनुपात का पूरे कालखंड में लगभग 41% के आसपास स्थिर बना रहना यह सिद्ध करता है कि बैंक ने ऋण वितरण और जोखिम प्रबंधन के मध्य संतुलन की नीति को सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया है। तरलता अनुपात का 1.59 से 1.63 तक पहुँचना यह दर्शाता है कि अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति हेतु बैंक के पास पर्याप्त तात्कालिक परिसंपत्तियों का संबल विद्यमान है,** जो उसके वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन **की दक्षता को पुष्ट करता है।**

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) का **17% से ऊपर स्थिर रहना इस तथ्य का प्रमाण है कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों से कहीं अधिक पूँजी भंडारित रखता है,** जिससे यह बैंक आकस्मिक वित्तीय **जोखिमों का सामना करने में सक्षम एवं वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है। यही नहीं,** प्रति कर्मचारी व्यापार में वृद्धि जो **₹167** लाख से **₹217** लाख तक पहुँची **यह दर्शाती है कि बैंक के मानव संसाधनों की** उत्पादकता, प्रशिक्षण **तथा कार्यनिष्ठा में निरंतर सुधार हुआ है। कुल व्यवसाय में हुई वार्षिक प्रगति यह दर्शाती है कि बैंक ने न केवल भौगोलिक विस्तार किया, बल्कि ग्रामीण समाज के भीतर विश्वास और पहुँच को भी मजबूत** किया है।

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की दिशा में उठाए गए नवाचारात्मक कदम जैसे मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सेवाएँ, एवं आधार-आधारित लेनदेन **से ग्राहक सेवा में गति, पारदर्शिता और संतुष्टि का स्तर भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। संपूर्ण विश्लेषण इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि बैंक ने वित्तीय रणनीतियों, संरचनागत व्यवस्थाओं तथा**

संचालन प्रक्रियाओं में दूरदर्शिता, उत्तरदायित्व और ग्रामीण संवेदनशीलता को एकीकृत करते हुए ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं जो उसे दीर्घकालिक वित्तीय स्थायित्व एवं सतत विकास की ओर अग्रसर करती हैं।

द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित यह अध्ययन इस तथ्य को पुष्ट करता है कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने विगत वर्षों में वित्तीय अनुशासन, प्रभावी प्रबंधन और जनकेंद्रित सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में अपनी एक सशक्त, विश्वसनीय और उत्तरदायी छवि निर्मित की है।

सुझाव:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाओं को सुलभ और ग्राहकों के लिए सरल बनाया जाए।
2. ऋण वसूली प्रणाली को अधिक सशक्त और समयबद्ध किया जाए जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) को न्यूनतम रखा जा सके।
3. स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्यमों और कृषकों को प्राथमिकता देते हुए ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और त्वरित किया जाए।
4. कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि वे तकनीकी रूप से दक्ष और ग्राहक सेवा में कुशल बनें।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को बैंकिंग, बचत, बीमा और निवेश की जानकारी दी जाए।
6. ग्राहक सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और शिकायत निवारण प्रक्रिया को प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाया जाए।
7. बैंकिंग निर्णयों के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण और आंकड़ों आधारित रणनीति को अपनाया जाए ताकि योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।
8. दूरदराज़ क्षेत्रों में टेली-बैंकिंग और स्थानीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का विकास किया जाए।
9. बैंक को माइक्रो-बीमा, माइक्रो-पेंशन, एजेंट बैंकिंग जैसी नवाचार आधारित सेवाओं को शुरू करना चाहिए ताकि ग्राहकों को वैकल्पिक सेवाएँ मिल सकें।
10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और जल-संरक्षण जैसे क्षेत्रों में बैंक को सक्रिय योगदान देना चाहिए।

उपसंहार:

मध्यांचल ग्रामीण बैंक के वित्तीय प्रबंधन पर आधारित इस शोधकार्य के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि एक सशक्त, उत्तरदायी और दूरदर्शी वित्तीय रणनीति किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संचालन, विकास और समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को किस प्रकार दिशा देती है। अध्ययन में प्रस्तुत आँकड़ों, विश्लेषणों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं से यह सिद्ध होता है कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने अपने सीमित संसाधनों के बीच भी वित्तीय अनुशासन, तकनीकी नवाचार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुपालन करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है।

बैंक की लाभप्रदता, ऋण वितरण क्षमता, तरलता की स्थिति, पूंजी पर्याप्तता तथा प्रति कर्मचारी व्यापार जैसे विविध अनुपातों के विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि बैंक की संरचना सुदृढ़ है और वह समय की माँग के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर, सांख्यिकीय विश्लेषणों ने यह स्पष्ट किया कि बैंक के

कर्मचारीगण और अधिकारीगण वित्तीय प्रक्रियाओं, ग्राहक सेवा और तकनीकी नवाचारों के संदर्भ में सजग और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।

इस शोध से यह भी ज्ञात हुआ कि डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता, ऋण वसूली प्रणाली और ग्राहक सेवा में अभी भी सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। यह निष्कर्ष इस बात का परिचायक है कि यदि बैंक इन सुझावों पर अमल करता है, तो वह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक संरचना को सशक्त बनाएगा बल्कि एक आदर्श ग्रामीण बैंक के रूप में उभर कर सामने आएगा।

यह शोध यह प्रतिपादित करता है कि वित्तीय प्रबंधन कोई मात्र तकनीकी प्रक्रिया नहीं है वरन् यह एक सतत, जागरूक और उत्तरदायी प्रयास है, जो बैंक को सामाजिक विकास, आर्थिक न्याय और समावेशी प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2021). **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट**. https://rbi.org.in
2. नाबार्ड. (2020). **भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण** बैंकों की स्थिति. मुंबई: **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास** बैंक.
3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2022). **क्षेत्रीय** ग्रामीण बैंकों पर वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली.
4. पांडे, आई. एम. (2019). वित्तीय प्रबंधन. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस.
5. गुप्ता, एस. पी., & अग्रवाल, एस. (2015). सांख्यिकीय विधियाँ. नई दिल्ली: सुल्तान चंद एंड संस.
6. शर्मा, एम., & गोयल, आर. (2013). **क्षेत्रीय** ग्रामीण बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु रणनीतियाँ. **जर्नल** ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 45(2), 102–115.
7. मिश्रा, आर. के. (2018). **क्षेत्रीय ग्रामीण** बैंकों में ऋण जोखिम एवं लाभप्रदता का अध्ययन. **इंडियन** जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग, 12(1), 65–80.
8. कुलकर्णी, ए. एम. (2023). **सार्वजनिक एवं निजी बैंकों में सेवा गुणवत्ता का ग्राहक संतुष्टि पर प्रभाव** (प्रबंध में पीएच.डी. शोधप्रबंध, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे).
9. जैन, एन., & सिंघई, एम. (2020). **मध्य प्रदेश में आरआरबी की वित्तीय स्थिति पर एनपीए का प्रभाव**. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, 11(4), 54–68.
10. जोशी, वी., & ठाकुर, ए. (2020). **भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन**: एक अवलोकन. **साउथ एशियन जर्नल** ऑफ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, 8(2), 88–100.
11. कुमार, ए., & यादव, एस. (2018). **कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यप्रणाली**. मुंबई: **हिमालय पब्लिशिंग हाउस**.
12. जोशी, वी., & जैन, एस. सी. (2016). **मध्य प्रदेश के आरआरबी के वित्तीय अनुपातों का तुलनात्मक अध्ययन**. **एमपी जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स**, 6(1), 42–58.
13. मध्यांचल ग्रामीण बैंक. (2020–2025). **वार्षिक प्रतिवेदन**. https://mpgb.in
14. परशुरामुलु, बी., & नाइक, डी. एन. (2013). भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन. **नाबार्ड एवं आरबीआई** वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर शोध, 2009–12.
15. चौहान, स्वाति. (2014). **मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेशन का अन्वेषणात्मक अध्ययन. इंडियन जर्नल** ऑफ सोशल साइंसेज़, 9(3), 134–150.